

14

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-10) विभाग

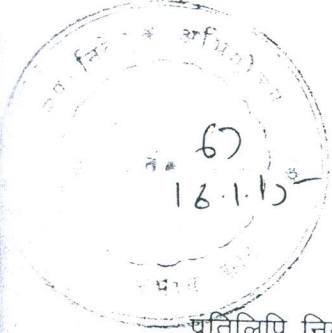
क्रमांक : 11(57)विविध/गृह-10/2014


जयपुर, दिनांक : 8.1.15

परिपत्र

अभि. 2015
16.1.15


यत् यह राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि फौजदारी प्रकरणों में लम्बित विचारण के दौरान मुल्जिम अनुपस्थित होने पर अथवा गवाहों को तलब करने के लिए जारी आदेशिकाओं (सम्मन/वारण्ट) पर यह रिपोर्ट आती है कि उक्त पते पर, इस नाम का व्यक्ति नहीं रहता। अधिकांश प्रकरणों में गवाहों के सम्मन बार-बार जारी होने पर भी तामील नहीं होते, जिससे प्रकरण का त्वरित विचारण नहीं हो पाता है। इसलिये न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले कम्प्यूटरीकृत आरोप पत्र में मुल्जिम व गवाह की सूची में उनका स्थाई पता व वर्तमान पता, मोबाईल नं० व लेण्ड-लाईन नं०, ई-मेल पता एवं यथा संभव मुल्जिम और गवाह की कम्प्यूटरीकृत फोटो भी चस्पा की जावे, जिससे उनकी पहचान के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अडचन पैदा न हो। गवाहों के टेलीफोन नं० व ई-पता आरोप पत्र में लिखे जाने से अभियोजन अधिकारी गवाह को टेलीफोन करके या ई-मेल करके भी तलब कर सकता है।




(राजेन्द्र सिंह चौधरी)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त परिपत्रानुसार न्यायालय में पेश किये जाने वाले आरोप पत्र में उक्त कार्यवाही समाविष्ट करना सुनिश्चित करे।
4. समस्त उप निदेशक अभियोजन।
5. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन।
6. रक्षित पत्रावली।


विशिष्ट शासन सचिव, गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी